



सत्ता परिवर्तन के बाद पश्चिम बंगाल में नई प्रशासनिक संरचना, विभागों के बंटवारे से शासन की दिशा हुई स्पष्ट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब नई सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह आकार देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेन्द्र अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने मंत्रिपरिषद के विभागों का औपचारिक बंटवारा कर शासन व्यवस्था की नई रूपरेखा सामने रख दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी अधिसूचना के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि नई सरकार किन प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ने वाली है और किस मंत्री को किस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विभागों का यह बंटवारा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सरकार की विकास नीति, राजनीतिक रणनीति और भविष्य की कार्ययोजना का भी संकेत है। नई सरकार के गठन के बाद से ही यह चर्चा चल रही थी कि महत्वपूर्ण मंत्रालयों की कमान किन नेताओं को मिलेगी। एक जून को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, जिसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद का आकार बढ़कर 41 सदस्यों का हो गया। इसके बाद विभागों के आवंटन का इंतजार किया जा रहा था। अब जारी आदेश ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री शुभेन्द्र अधिकारी ने अपने पास

कई महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार के शुरुआती चरण में वे प्रशासनिक नियंत्रण और नीतिगत फैसलों पर सीधी निगरानी बनाए रखना चाहते हैं। गृह एवं पर्वतीय मामले, भूमि एवं भूमि सुधार, शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास, बिजली, सूचना एवं संस्कृति तथा कर्मिक एवं प्रशासनिक सुधार जैसे विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिन विभागों का आवंटन किसी अन्य मंत्री को नहीं किया गया है, उनकी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री स्वयं संभालेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन विभागों का महत्व राज्य की सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार, विकास योजनाओं और राजनीतिक संतुलन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।



मंत्रिमंडल में शामिल वरिष्ठ नेताओं को भी उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उत्तर बंगाल की राजनीति में प्रभाव रखने वाले निशेथ प्रामाणिक को उत्तर बंगाल विकास तथा जन संसाधन जांच एवं विकास विभाग की जिम्मेदारी देकर क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है। उत्तर बंगाल लंबे समय से विकास और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा है, ऐसे में यह विभाग सरकार की

सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और पंचायत व्यवस्था राज्य की राजनीति का अहम आधार मानी जाती है। आदिवासी और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से खुर्दिराम टुडू को आदिवासी विकास, अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभाग दिया गया है। वहीं अग्निमित्रा पाल को शहरी विकास एवं नगर मामलों का विभाग सौंपा

सरकार की प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं। प्रबंधन करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एवं उद्यम, सार्वजनिक उपक्रम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण तथा गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग देकर राज्य में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने का दायित्व सौंपा गया है। पर्यटन क्षेत्र को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से शंकर घोष को पर्यटन और संसदीय कार्य विभाग का प्रभार दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग से लेकर सुंदरबन तक कई विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल मौजूद हैं। सरकार को उम्मीद है कि पर्यटन क्षेत्र के विस्तार से रोजगार और राजस्व दोनों में वृद्धि होगी। इसी क्रम में मनोज कुमार उरांव को वन एवं पर्यावरण विभाग तथा अर्जुन सिंह को श्रम एवं परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को जगन्नाथ चट्टोपाध्याय के हवाले किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में रोजगार और कौशल विकास सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होंगे, इसलिए यह विभाग विशेष महत्व रखता है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता स्वपन दासगुप्ता को सौंपी गई है। राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, राजस्व बढ़ाना

और विकास योजनाओं के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवानी विभाग कल्याण चक्रवर्ती को दिए गए हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी निवेश को आकर्षित करने में इन विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी शरद्वत मुखर्जी को सौंपी गई है, जबकि सिंचाई एवं जलमग्न विभाग अरुण कुमार दास और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा लोक निर्माण विभाग अजय कुमार पोद्दार को दिया गया है। कृषि विभाग का प्रभार दूध कुमार मंडल को सौंपा गया है। सरकार ने महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार जैसे सामाजिक कल्याण से जुड़े विभाग मालती राव रॉय को दिए हैं। पशु संसाधन विकास एवं मत्स्य विभाग राजेश महाता को तथा युवा कल्याण एवं खेल तथा उपभोक्ता मामलों विभाग इंद्राणी खान को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कई राज्य मंत्रियों को विभिन्न विभागों में सहयोगी जिम्मेदारियां देकर प्रशासनिक संरचना को व्यापक बनाया गया

है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि विभागों का यह बंटवारा केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक संतुलन, संगठनात्मक अनुभव और राजनीतिक संदेश भी शामिल हैं। नई सरकार के सामने रोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे जैसे कई बड़े मुद्दे हैं। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मंत्रियों की यह नई टीम अपने-अपने विभागों में कितनी प्रभावी भूमिका निभाती है और सरकार जनता से किए गए वादों को किस गति से पूरा कर पाती है। विभागों के आवंटन के साथ ही पश्चिम बंगाल की नई सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। अब प्रशासनिक फैसलों, विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की दिशा में तेज गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सरकार का दावा है कि यह टीम मालती राव रॉय को दिए हैं। पशु संसाधन विकास एवं मत्स्य विभाग राजेश महाता को तथा युवा कल्याण एवं खेल तथा उपभोक्ता मामलों विभाग इंद्राणी खान को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कई राज्य मंत्रियों को विभिन्न विभागों में सहयोगी जिम्मेदारियां देकर प्रशासनिक संरचना को व्यापक बनाया गया

भाजपा की तमिलनाडु इकाई में बड़ी हलचल, वरिष्ठ नेता अमर प्रसाद रेड्डी के इस्तीफे से उठे संगठनात्मक सवाल

चेन्नई। तमिलनाडु भाजपा में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब पार्टी के प्रदेश सचिव अमर प्रसाद रेड्डी ने अपने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। पिछले तेरह वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे रेड्डी के इस फैसले को राज्य इकाई के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं में उनकी पहचान और युवा चेहरों को जोड़ने वाले नेता के रूप में रही है। ऐसे में उनके अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अमर प्रसाद रेड्डी ने अपना इस्तीफा तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष को भेजते हुए स्पष्ट किया कि वह पार्टी के सभी आधिकारिक दायित्वों से तत्काल प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं। उनके इस कदम के साथ भाजपा और उनके बीच करीब तेरह वर्षों का राजनीतिक सफर समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में पार्टी के

शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त किया, लेकिन साथ ही संगठन के भीतर उत्पन्न परिस्थितियों और कुछ व्यक्तित्व अनुभवों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया है जब भाजपा तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ने, युवाओं को जोड़ने और संगठनात्मक विस्तार की रणनीति के तहत कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। अमर प्रसाद रेड्डी उन नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने इन अभियानों को जमीनी स्तर पर गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेड्डी वर्ष 2013 में भाजपा से जुड़े थे। उस समय वे युवा कार्यकर्ता के रूप में संगठन में आए और धीरे-धीरे अपनी सक्रियता, संगठनात्मक क्षमता और कार्यक्रमों के सफल संवादन के कारण पार्टी नेतृत्व का विश्वास जीतते गए। उन्होंने पार्टी के स्पेक्ट्रस एवं स्थूल डेवलपमेंट

सेल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और युवाओं के बीच भाजपा की पहुंच बढ़ाने के लिए कई अभियान पहले शुरू कीं। उनकी सबसे चर्चित उपलब्धियों में मोदी कबड्डी लीग का आयोजन शामिल रहा। इस कार्यक्रम को भाजपा की युवा संपर्क रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया था। बताया जाता है कि इस आयोजन में 60 हजार से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिससे पार्टी को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नए कार्यकर्ताओं और सदस्यों तक पहुंच बनाने में मदद मिली। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार यह कार्यक्रम केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि युवाओं को राष्ट्रवाद, नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के संदेशों से जोड़ने का प्रयास भी था। इसके अतिरिक्त अमर प्रसाद रेड्डी ने भाजपा की चर्चित 'एन मन्न एन मक्कल यात्रा' के आयोजन में भी केंद्रीय भूमिका निभाई। इस यात्रा को तमिलनाडु में भाजपा के विस्तार अभियान का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।

यात्रा के दौरान राज्य के सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था। रेड्डी ने इस अभियान के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए लगभग 9,800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। इस यात्रा का उद्देश्य जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और भाजपा की नीतियों को सीधे लोगों तक पहुंचाना था। राजनीतिक गतिविधियों के अलावा रेड्डी ने वैचारिक स्तर पर भी पार्टी के लिए योगदान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकास दृष्टि को केंद्र में रखकर 'वणक्कम तमिझगम' और 'कनोविटिंग 1.4 बिलियन' जैसी पुस्तकों को लेखन किया। इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजनीति के बीच संबंधों तथा प्रधानमंत्री के विकास मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। पार्टी के भीतर उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता था जो संगठनात्मक कार्यों के साथ-साथ वैचारिक विमर्श में भी सक्रिय रहते थे।

नामांकन विवाद से गरमाई सियासत, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने पर कांग्रेस का तीखा हमला

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस निर्णय को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए इसे राजनीतिक प्रेरित कार्रवाई करार दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान नियमों और कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया है। इस घटनाक्रम ने राज्यसभा चुनाव को लेकर नई बहस छेड़ दी है और राजनीतिक गलियारों में इसके दूरगामी प्रभावों पर चर्चा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होने हैं। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पहले से लगभग तय मानी जा रही थी, जबकि तीसरी सीट पर मुकाबला अपेक्षाकृत रोचक माना जा रहा था। कांग्रेस ने इस सीट के



लिए अनुभवी नेता मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा था, जबकि भाजपा ने महेश केवट को उम्मीदवार बनाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि तीसरी सीट पर दोनों दलों के बीच रणनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन नामांकन पत्र खारिज होने के बाद चुनावी समीकरण अचानक बदल गए हैं। नामांकन रद्द होने के बाद अब भाजपा उम्मीदवार महेश केवट के राज्यसभा पहुंचने का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक

प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत कर रही है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि विपक्षी उम्मीदवार को चुनावी मैदान से बाहर करने के लिए नियमों की ऐसी व्याख्या की गई, जिससे निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। विवाद की जड़ वर्ष 2022 की एक शिकायत को बताया जा रहा है। उस समय कांग्रेस नेता शिव कुमार रेड्डी के खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ और धमकी से संबंधित आरोप लगाए थे। इस मामले में मीनाक्षी नटराजन किसी भी एफआईआर में आरोपी नहीं थीं और न ही उनके खिलाफ किसी आपराधिक प्रकरण में प्रत्यक्ष रूप से आरोप तय किए गए थे। हालांकि शिकायतकर्ता महिला का दावा था कि उसने पार्टी नेतृत्व को भी इस संबंध में शिकायत भेजी थी, जिसमें मीनाक्षी नटराजन का नाम भी संदर्भ के रूप में शामिल था। महिला ने यह आरोप लगाया था कि उसकी शिकायत पर

संगठनात्मक स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा ने इसी बिंदु को आधार बनाते हुए यह तर्क रखा कि मामले से संबंधित एक याचिका अदालत में लंबित है और उसमें मीनाक्षी नटराजन का उल्लेख किया गया है। भाजपा का कहना है कि चुनावी नामांकन के दौरान उम्मीदवारों को अपने संबंध में उपलब्ध सभी प्रासंगिक जानकारीयां घोषित करनी होती हैं। पार्टी नेताओं का दावा है कि यदि किसी न्यायिक प्रक्रिया में किसी उम्मीदवार का नाम आता है, तो उससे संबंधित जानकारी चुनावी दस्तावेजों में दी जानी चाहिए ताकि निर्वचन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के इस तर्क को पूरी तरह खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला दर्ज है और न ही था कि उसने पार्टी नेतृत्व को भी इस संबंध में शिकायत भेजी थी, जिसमें मीनाक्षी नटराजन का नाम भी संदर्भ के रूप में शामिल था। महिला ने यह आरोप लगाया था कि उसकी शिकायत पर

लोकतंत्र की लंबी यात्रा में नया अध्याय: सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय उस समय जुड़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में यह उपलब्धि केवल एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक यात्रा, जनविश्वास और बदलते राजनीतिक परिदृश्य का भी प्रतीक मानी जा रही है। लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले नेताओं की सूची में अब नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और सबसे लंबे समय तक जनता द्वारा निर्वाचित होकर शासन करने वाले प्रधानमंत्रियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया है। आजादी के बाद भारत ने अनेक राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। देश ने गठबंधन सरकारों का दौर भी देखा, राजनीतिक अस्थिरता भी देखी और मजबूत जनादेश वाली सरकारों का समय भी देखा। ऐसे में लगातार तीन बार जनता का विश्वास



प्राप्त कर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना और वर्षों तक उस विश्वास को बनाए रखना अपने आप में एक असधारण उपलब्धि मानी जाती है। नरेंद्र मोदी ने इसी क्रम में वह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो दशकों तक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की नींव रखने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा तय करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उन्होंने ऐसे समय में देश का नेतृत्व किया जब भारत विभाजन के घावों, आर्थिक चुनौतियों और प्रशासनिक मुद्दों का आधारभूत संरचना तैयार हुई। इसके बाद विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने अपने-अपने समय में देश को नई दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का रिकॉर्ड लंबे समय तक अटूट बना रहा। अब नरेंद्र मोदी ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारतीय राजनीति में एक नया मानदंड स्थापित कर दिया है। वर्ष 2014 में

पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2019 और फिर 2024 में भी जनता का विश्वास प्राप्त किया। लगातार तीन आम चुनावों में मिली सफलता ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह उपलब्धि केवल ऐसे नेतृत्व की स्वीकार्यता को भी दर्शाती है जिसने राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में विकास, राष्ट्रवाद, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक प्रतिष्ठा जैसे मुद्दों को स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव देखे हैं। देश में बुनियादी ढांचे के विस्तार को अभूतपूर्व गति मिली है। एक्सप्रेसवे, रेलवे आधुनिकीकरण, हवाई अड्डों का विस्तार और बंदरगाहों के विकास जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश हुए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने शासन और नागरिक सेवाओं के स्वरूप को बदल दिया है। आज करोड़ों लोग डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच

बढ़ाने को भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी सरकार ने कई बड़े सुधारों को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया है। जीएसटी लागू करने से लेकर वैश्विक सुधार, स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने तक अनेक कदम उठाए गए। सरकार का दावा है कि इन सुधारों ने भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया है। हाल के वर्षों में भारत ने वैश्विक मंचों पर भी अपनी उपस्थिति को अधिक प्रभावशाली बनाया है। जी-20 की अध्यक्षता, वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भूमिका और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी को मोदी सरकार की कूटनीतिक उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस रिकॉर्ड को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा के भीतर उत्साह का माहौल देखा गया। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक विशेष बैठक में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और गठबंधन दलों के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर शामिल हुए। नेताओं ने इसे भारतीय लोकतंत्र में जनता के निरंतर विश्वास का प्रतीक बताया। इसी अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के बारह वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को समर्पित एक विशेष बुकलेट भी जारी की गई। इसमें कर



नवसर्जन संस्कृति

हिन्दी

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

संपादकीय

बड़े बदलावों संग विकसित भारत का संकल्प

सत्ता शीर्ष पर बारह साल के कार्यकाल के दौरान अनेक विशिष्ट उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में आई हैं। एक विशेष उपलब्धि यह भी है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पं. नेहरू ने पहले आम चुनाव के बाद 13 मई, 1952 को विधिवत निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल शुरू किया, जो 1964 तक चला। वहीं नरेंद्र मोदी ने 26 मई, 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ 9 जून, 2024 को ली। निश्चय ही भारत जैसे विशाल, सांस्कृतिक विविधता वाले तथा दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश का इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहना एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। भाजपा नीत राजग गठबंधन सरकार के हिस्से में यूं तो कई उपलब्धियां हैं, लेकिन एक सशक्त केंद्र सरकार देश की एकता-अखंडता के लिए प्रतिबद्ध रही है। निस्संदेह, मोदी युगीन इन बारह सालों को अनुच्छेद-370 हटाने, नक्सलवाद के खान्ते, आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक सुरक्षा नीति, आध्यात्मिक पर्यटन, महिला आरक्षण, डिजिटल इंडिया मुहिम, तीन तलाक से मुक्ति व आर्थिक आरक्षण की उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। निस्संदेह, कुछ फैसले ऐसे रहे हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी। लोगों को गरिमा व अवसर दिलाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं बदलावकारी कही जाती हैं। साथ ही उन लोगों को ‘अंत्योदय दूधिट’ से प्रेरित होकर लाभ देने की कोशिश हुई, जो असमानता के चलते पीछे छूट गए थे। बड़ी संख्या में जनधन खाते खोले जाने का लाभ विशेष रूप से महिलाओं को मिला। जहां डायरेक्ट बेंचिफट ट्रांसफर से जहां लोगों को समय पर मदद मिली, वहीं बिजौलियों पर नकेल कसने से भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा। मोदी सरकार ने ‘एक देश, एक कर’ की सोच को जीएसटी लागू करके हकीकत बनाया।

जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजे थे तो उन्होंने उद्घोष किया था कि न ‘खाऊंगा और न खाने दूंगा।’ यह हकीकत है मानवीय दुर्बलताओं और समाज में लगातार बढ़ती भौतिकवाद की सोच के चलते समाज में भ्रष्टाचार पर अपेक्षित लगाम नहीं लगी, लेकिन उनके कार्यकाल में कोई मंत्री प्रत्यक्ष तौर पर किसी बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त नजर नहीं आया। निस्संदेह, खाड़ी संकट के चलते हमेंगे हुए पेट्रोलियम पदार्थों से महंगाई असर दिखा रही है, लेकिन समय रहते प्रबंधन के चलते वैैसे हालात भी नहीं पैदा हुए, जैसे हमारे पड़ोसी देशों में नजर आ रहे हैं। अमेरिका दबाव के बावजूद रणनीतिक ढंग से रूस से सस्ता तेल खरीदकर मोदी सरकार ने जहां देश के आपातकालीन पेट्रोलियम भंडारण को बढ़ाया, वहीं दुर्लभ विदेशी मुद्रा की भी बचत की। आज देश ने कच्चे तेल के खरीद के विकल्पों को विस्तार दिया है, जो संकटकाल में मददगार साबित हुए हैं। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री द्वारा सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा आदि वैकल्पिक संसाधनों के लिए जो अभियान चलाए गए, उन्होंने पश्चिम एशिया संकट के दौरान देश की आर्थिकों को संबल दिया। एक समय विपक्षी नेता पेट्रोल में एथनॉल मिलाए जाने को लेकर आलोचना कर रहे थे, लेकिन यह फैसला मौजूदा ऊर्जा संकट में मददगार साबित हुआ। भारत एक विकासशील देश है, बड़ी आबादी जहां इसकी ताकत है, वहीं कमजोरी भी है। देश के अरसी करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना जहां एक बड़ी उपलब्धि है, वहीं लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए एहल करने को भी रेखांकित करता है। हालांकि, कोरोना संकट, रूस-यूक्रेन युद्ध, इस्राइल-हमास संघर्ष और फिर ईरान अमेरिका-इराक़ युद्ध के संकट से पूरी दुनिया की आपूर्ति थंखला बुरी तरह प्रभावित हुई है, लेकिन राजग सरकार इन चुनौतियों का बखूबी मुकाबला करती नजर आई। इसके बावजूद मोदी सरकार की फिनहाल बरोजगारी व महंगाई पर अंकुश लगाना प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत युवाओं का देश है, इस युवाशक्ति का देश हित में कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, इसकी दृष्टि, इसकी साधन ही प्रधानमंत्री के पास है। तभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

अभियान

मानव जीवन केवल सांस लेने, भोजन करने और भौतिक सुख-सुविधाओं को प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। यह ऐसा होता तो मनुष्य और अन्य जीवों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य को प्रकृति ने एक ऐसी चेतना प्रदान की है, जो उसे अपने अस्तित्व के अर्थ पर विचार करने, सही और गलत में भेद करने तथा अपने जीवन को किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने की क्षमता देती है। यही चेतना धर्म का आधार है। धर्म मनुष्य के जीवन की वह आंतरिक शक्ति है जो उसे केवल जीवित रहने की कला नहीं, बल्कि सार्थक और श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। धर्म का संबंध किसी विशेष वेशभूषा, पूजा-पद्धति या परंपरा से अधिक मनुष्य के चरित्र, व्यवहार और दृष्टिकोण से है। जब धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप में समझा जाता है, तब वह व्यक्ति, समाज और समूची मानवता के विकास का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। आज के समय में धर्म को लेकर अनेक भ्रम दिखाई देते हैं। कुछ लोग धर्म को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित मानते हैं, जबकि कुछ इसे केवल सामाजिक पहचान के रूप में देखते हैं। वास्तव में धर्म का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। संस्कृत में ‘धर्म’ शब्द की उत्पत्ति ‘धृ’ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है—धारण करना। इस अर्थ को जीवन को धारण करे, जो समाज

रेडियो ने एकता के सूत्र में पिरोया देश को

“ गत 90 वर्षों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, संसदीय व निर्वाचन गतिविधियों, विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में रेडियो ने सेतु की भूमिका निभाई।

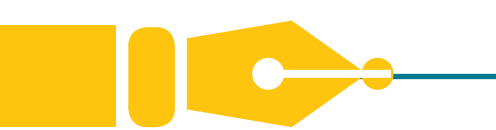
प्रेरणा

जीवन में असफलता को अक्सर अंत समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में वह एक नई शुरुआत का द्वार होती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को बदलने का साहस किया, उन्हें भी कभी न कभी हार, अपमान और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि वे कभी गिरे नहीं, बल्कि इस बात में थी कि हर गिरावट के बाद वे पहले से अधिक शक्ति और आत्मविश्वास के साथ खड़े हुए। स्टीव जॉब्स का जीवन इसी सत्य का जीवंत उदाहरण है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हार जीवन की अंतिम मंजिल नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसा मोड़ होती है जहाँ से सफलता का नया रास्ता निकलता है।

स्टीव जॉब्स का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद उन्हें गोद दे दिया गया था। बचपन से ही उनके जीवन में कई प्रकार की चुनौतियाँ थीं। आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत मजबूत नहीं थीं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना भी उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने कॉलेज में दाखिला तो लिया, लेकिन फीस का खर्च वहन करना मुश्किल हो गया। परिणामस्वरूप उन्हें पहाई बीच में छोड़नी पड़ी। कई बार वे मित्रों के कमरों में फर्श पर सोते थे और भोजन के लिए कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें बेचकर पैसे जुटाते थे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने उनके सपनों को कमजोर नहीं किया। उनके भीतर कुछ नया करने की आग लगातार जलती रही।

साल 1976 में उन्होंने अपने मित्र स्टीव वॉजिनयाक के साथ एक छोटे से गैराज में ‘एप्पल’ कंपनी की शुरुआत की। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि वह छोट-सा

दिस इज ऑल इंडिया रेडियो...’ यह वाक्य केवल एक उद्घोषणा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की स्मृतियों, संवेदनाओं और राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न हिस्सा है। रेडियो ने भारत को केवल समाचार नहीं दिए, बल्कि उसे एक सूत्र में पिरोने, संस्कृति को संरक्षित करने, लोकतंत्र को मजबूत बनाने और संकट के समय जनविश्वास कायम रखने का कार्य किया। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। इस संस्था ने अपनी गौरवशाली 90 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1921 से 1924 के मध्य रेडियो क्लबों के माध्यम से शुरू हुई। 23 जुलाई, 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बंबई और कलकत्ता से नियमित प्रसारण प्रारंभ किया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकी। वर्ष 1932 में भारत की अंग्रेज सरकार ने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम से प्रसारण व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। सितंबर, 1935 में एक अंग्रेज ब्रॉडकास्टर एलियोनेल फ़ोल्डन को लंदन से भारत बुलाकर प्रसारण नियंत्रक बनाया गया। उन्होंने 1 जनवरी, 1936 को दिल्ली के 18, अलीपुर रोड स्थित एक छोटे से भवन से इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का संचालन शुरू किया। फ़ोल्डन को यह नाम आकर्षक नहीं लगता था। एक अवसर पर उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो से अपनी समस्या साझा की। लिनलिथगो ने उनका सुझाया—‘ऑल इंडिया रेडियो’। 8 जून, 1936 को पहली बार यह उद्घोषणा प्रसारित हुई और भारतीय प्रसारण इतिहास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। 90 वर्षों में



हार नहीं, नई उड़ान की शुरुआत

प्रयास एक दिन दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन जाएगा। जॉब्स के पास नहीं था, लेकिन उनके पास दूरदर्शिता, रचनात्मक सोच और असेंभर को संभय बनाने का जुनून था। उन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में ऐसे बदलाव लाने का सपना देखा जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके। उनकी मेहनत और नवाचार के कारण एप्पल तेजी से आगे बढ़ी। कुछ ही वर्षों में कंपनी अरबों डॉलर की हो गई और हजारों लोगों को रोजगार देने लगी। जब सफलता अपने चरम पर थी, तभी जीवन ने उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। एप्पल के बॉर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स और जॉब्स के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद होने लगे। धीरे-धीरे यह मतभेद इतना बढ़ गया कि वर्ष 1985 में उन्हें उसी कंपनी से हटाकर दिया गया, जिसकी स्थापना उन्होंने अपने हाथों से की थी। यह घटना उनके लिए किसी भूकंप से कम नहीं थी। जिस कंपनी को उन्होंने अपने सपनों, मेहनत और संघर्ष से खड़ा किया था, उसी से उन्हें निकाल दिया गया। यह केवल नौकरी खोने का मामला नहीं था, बल्कि यह खर्च वहन करना मुश्किल हो गया। परिणामस्वरूप उन्हें पहाई बीच में छोड़नी पड़ी। कई बार वे मित्रों के कमरों में फर्श पर सोते थे और भोजन के लिए कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें बेचकर पैसे जुटाते थे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने उनके सपनों को कमजोर नहीं किया। उनके भीतर कुछ नया करने की आग लगातार जलती रही।

साल 1976 में उन्होंने अपने मित्र स्टीव वॉजिनयाक के साथ एक छोटे से गैराज में ‘एप्पल’ कंपनी की शुरुआत की। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि वह छोट-सा

मामाज में संतुलन और समरसता बनी रहती है। इसलिए धर्म को समाज की नैतिक रीढ़ कहा गया है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य धर्म के व्यावहारिक स्वरूप को समझाने के लिए अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्रीराम का जीवन धर्म की जीवंत व्याख्या है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन सभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। राज्याभिषेक की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन पिता की आज्ञा और सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने नवाास स्वीकार कर लिया। यह केवल एक राजकुमार का त्याग नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि धर्म का पालन परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। श्रीराम के जीवन धर्म का कठिन चरित्र एक सीमित नहीं था। उसमें करुणा, विनम्रता और लोकमंगल की भावना भी शामिल थी। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय में समाज और मर्यादा को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि उन्हें केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक पात्र नहीं, बल्कि आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि धर्म मनुष्य को महान बनाता है और उसके व्यक्तित्व को कालातीत बना देता है। लक्ष्मण का चरित्र धर्म के प्रति समर्पण और उनका निष्ठापूर्वक पालन करता है, तब



आकाशवाणी भारत की संस्कृति, सभ्यता और देश की पहचान बनी, जिस पर प्रत्येक भारतीय गर्व करता है। ऑल इंडिया रेडियो ने भारत की संगीत और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में अमूल्य योगदान दिया। रेडियो नाटक जैसी नई विधा का विकास भी इसी माध्यम से हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में, विशेषकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भूमिगत रेडियो प्रसारणों ने जनचेतना को बल दिया। 3 जून, 1947 को भारत विभाजन की घोषणा प्रसारण, दिल्ली से हुई। 14-15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि को संविधान

सभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक ‘नियति से मिलन’ भाषण ऑल इंडिया रेडियो ने देश-दुनिया तक पहुंचाया। भारत विभाजन की त्रासदी के समय, विस्थापित लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने और प्रशासनिक सूचनाएं और निर्देश देने में रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12 नवंबर, 1947 को महान्या गांधी ने प्रसारण भवन, दिल्ली आकर कुरुक्षेत्र में बसे शरणार्थियों को संबोधित किया था। 12 नवंबर को लोकसेवा प्रसारण दिवस मनाने की घोषणा तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने की थी।

स्वतंत्रता के बाद विविधताओं से भरे भारत

में आईकैम, आईफॉंड, आईफोन और बाद में आईपैड जैसे क्रांतिकारी उत्पाद दुनिया के सामने आए। इन उत्पादों ने केवल तकनीक को नहीं बदला, बल्कि लोगों के जीने, काम करने और संवाद करने के तरीकों को भी बदल दिया। एप्पल फिर से दुनिया की अग्रणी कंपनियों में शामिल हो गई और जॉब्स आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली नवप्रवर्तकों में गिने जाने लगे। स्टीव जॉब्स ने बाद में अपने जीवन के उस कठिन दौर को याद करते हुए कहा था कि एप्पल से निकाला जाना उनकी जिंदगी की सबसे कड़वी दवा थी, लेकिन उसी ने उन्हें नया जीवन दिया। यदि उन्हें कंपनी से नहीं निकाला गया होता, तो शायद वे कभी फिक्स नहीं बनाते, नई तकनीकों का विकास नहीं करते और अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पूरी तरह नहीं पहचान पाते। उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी जीवन हमें उस रास्ते से हटाता है जिसे हम सही समझते हैं, ताकि हम उस रास्ते पर चल सकें जो वास्तव में हमारे लिए बना होता है। उनकी कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब हम असफल होते हैं, तब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता अक्सर सफलता का नया अध्याय लिखने की तैयारी होती है। हार हमें हमारी कमजोरियाँ दिखाती है, हमें मजबूत बनाती है और नए अवसरों के लिए तैयार करती है। यदि हम धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास बनाए रखें, तो वही हार एक दिन हमारी सबसे बड़ी जीत का कारण बन सकती है। स्टीव जॉब्स का जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति गिरकर भी उठना जानता है, उसके लिए कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती।

उचित है। यही आंतरिक नैतिकता धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। महर्षि कणाद, याज्ञवल्क्य, मनु और अन्य भारतीय ऋषियों ने धर्म को जीवन का सर्वोच्च आधार माना है। उनके अनुसार धर्म वह साधन है जो व्यक्ति को सांसारिक जीवन में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। धर्म का उद्देश्य जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीना सिखाना है। यह संसार को त्यागने की नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। मनुस्मृति में धर्म के दस लक्षण बताए गए हैं—धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सत्य और अक्रोध। यदि इन गुणों को राजसिंहासन पर स्थापित किया। भरत का यह स्पष्ट होता है कि आज भी इनकी आवश्यकता उतनी ही है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मनुष्य को भीतर से बदलता है। कानून और नियम किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उसके विचारों और भावनाओं को नहीं। धर्म मनुष्य के अंतःकरण को जागृत करता है। वह उसे यह समझाने की प्रेरणा देता है कि सही कार्य इसलिए नहीं करना चाहिए कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि वही

अज्ञ तकनीक ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद समाज में अकेलापन, असहिष्णुता और मानसिक अशांति बढ़ती जा रही है।

हुई इस सेवा ने ‘हवा महल’, ‘जयमाला’, ‘छायागीत’ और ‘भूले-बिसरे गीत’ जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम दिए। सैनिकों के लिए प्रसारित ‘जयमाला’ आज भी भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। 3 अक्तूबर, 1957 को ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी नाम ‘आकाशवाणी’ रखा गया। वर्ष 1962 के चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध, कारगिल संघर्ष तथा अनेक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों का सबसे भरोसेमंद माध्यम आकाशवाणी ही रही। आकाशवाणी को समृद्ध बनाने में लियोनेल फ़ोल्डन, बुखारी बंधु, जगदीश चंद्र माथुर, पंडित नरेंद्र शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, उपेंद्र अश्क, पंडित रवि शंकर, दिनेश विश्वास, मेनविल डी मेलो, गिरिजा कुमार माथुर, दुष्यंत कुमार, जसदेव सिंह, देवकीनंदन पाण्डेय, विनोद कश्यप, सुरजीत सेन, बोरुन हलदार और अनेक प्रतिभाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गत 90 वर्षों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, संसदीय गतिविधियों, निर्वाचन गतिविधियों, विकास योजनाओं और सरकारी नीतियां जनता तक पहुंचाने में रेडियो ने सेतु की भूमिका निभाई। विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, विज्ञान प्रसार और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। भूकंप, बाढ़, चक्रवात और महामारी जैसी परिस्थितियों में, जब अन्य संचार माध्यम बाधित हो जाते हैं, तब भी रेडियो प्रभावी ढंग से कार्य करता है। आकाशवाणी ने एफएम गोल्ट, एफएम रेनबो जैसी सेवाओं के माध्यम से नए श्रोताओं तक पहुंचाई। आज प्रसारण मोबाइल ऐप, वेब स्ट्रीमिंग, डिजिटल आकाईव और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर उपलब्ध हैं। जनता का विश्वास आकाशवाणी की सबसे बड़ी पूंजी है।

बेगुनाह जिंदगियों से खेलता भ्रष्ट तंत्र और दिल्ली के अंतहीन अग्निकांड

पिछले दिनों दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हमारे यहां हादसे अचानक नहीं होते बल्कि उन्हें पैदा किया जाता है। 21 लोगों की दर्दनाक मौत, दर्जनों घायल, धुएं में घुटती सांसें, तीसरी मंजिल से जान बचाने के लिए छलांग लगते लोग और बेसमेंट के बाहर बंद पड़ा निकास द्वार, यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता, भ्रष्ट व्यवस्था और नियमों की खुलेआम हत्या का भयावह परिणाम था। दुःखद यह है कि यह कोई नई कहानी नहीं है। दिल्ली बार-बार अग्निकांडों में जलती है, लोग बार-बार मरते हैं, जांच समितियाँ बनती हैं, मुआवजे घोषित होते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मालवीय नगर के हादसे में जो शुरुआती तथ्य सामने आए, वे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाले थे। जिस भवन में धुआं भर गया और निकास मार्ग अवरुद्ध हो गया, वह किसी भी सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई थी। उसी वर्ष गोकुलपुरी की झुग्गी बस्ती में आग से 7 लोगों की जान चली गई। 2024 में अलीपुर की अवैध पेंट फैक्ट्री में लगी आग में 11 लोगों की मौत हुई। 2026 में पालम और विवेक विहार में हुए अग्निकांडों में नौ-नौ लोगों की जान गई। अब मालवीय नगर की त्रासदी ने मुक्तों की सूची में 21 और नाम जोड़ दिए हैं। दिल्ली की अनुमति के बावजूद 25 से अधिक कमरे बनाए गए थे। भवन से निकासने का केवल एक रास्ता था। बेसमेंट में लोगों की मौजूदगी के बावजूद बाहरी गेट पर ताला लगा था। आग लगने के बाद धुआं इतनी तेजी से फैला कि लोग बाहर निकल ही नहीं सके। कुछ लोगों ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की, जो कई बार जान-बहार मरते हैं, जांच के अफसरों के रूप से तलाज कर गया, जहां-जहां निकलने के रास्ते बंद होने के कारण 59 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली में अग्निकांडों का इतिहास बताता है कि हर बड़ी त्रासदी के पीछे कहानी लगभग एक जैसी है, अवैध निर्माण, सुरक्षा मानकों को अनदेखी, भ्रष्टाचार, फर्जी प्रमाणपत्र, बंद निकास द्वार और प्रशासनिक लापरवाही। 13 जून 1997 को हुए उदाहर सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी, जो दिल्ली का अब तक का सबसे भयावह अग्निकांड माना जाता है। आग लगने के बाद सिनेमा हॉल केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मिक संतुलन में है। या गुरुद्वारे तक सीमित नहीं है। यह उन सभी कार्यों में प्रकट होता है, जिनमें मानवता और करुणा की भावना हो। भूखे को भोजन कराना, दुखी व्यक्ति को संत्वना देना, जरूरतमंद की सहायता करना, सत्य का प्रचार करना—ये सभी धर्म के ही रूप हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है लेकिन दूसरों के प्रति कठोर और अस्वेददर्शील है, तो उसकी पूजा अधूरी है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति मानव सेवा को अपना धर्म मानता है, तो वह वास्तविक धार्मिकता के अधिक निकट है। ध्यान, योग, प्रार्थना और आत्मचिंतन धर्म को जीवन में उतारने के प्रभावी साधन हैं। ये अभ्यास मनुष्य को अपने भीतर झाँकने का अवसर देते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को समझने लगता है, तब वह दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझ पाता है। उसका मन शांत होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण व्यापक बनता है।

नासीरनगर विवाद में नया मोड़, बिजली कटौती और तोड़फोड़ पर घिरी व्यवस्था, कांग्रेस ने उठाए जवाबदेही के सवाल

सूरत। वेड रोड स्थित नासीरनगर बस्ती में हुए व्यापक तोड़फोड़ अभियान के बाद अब मामला केवल अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक जवाबदेही, नागरिक अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं के प्रश्न से जुड़ा एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। सौ से अधिक कच्चे मकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद जहां प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं, वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम में नगर निगम और बिजली वितरण कंपनी की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि सूरत नगर निगम ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा इस प्रकार की कोई प्रत्यक्ष तोड़फोड़ कार्रवाई नहीं की गई थी। इस दावे के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस और तेज हो गई है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई किसके निर्देश पर और किस प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई। नासीरनगर में रहने वाले परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे थे और अनेक परिवारों

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक डिजिटल लगेज लॉकर सुविधा का शुभारंभ, यात्रियों को मिलेगा सुरक्षित, स्मार्ट एवं कैशलेस सामान भंडारण का विकल्प

यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित एवं विविधस्तरीय डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक ‘डिजिटल लगेज लॉकर सुविधा’ का शुभारंभ किया गया। इस नई सुविधा का उद्घाटन माननीय सांसद श्री दिनेशभाई मकवाना द्वारा किया गया। इस अवसर पर सांसद श्री दिनेशभाई मकवाना ने कहा कि यह स्वचालित डिजिटल लगेज लॉकर सुविधा यात्रियों को शहर भ्रमण अथवा अन्य कार्यों के दौरान अपने सामान को सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होगी। यात्री बिना किसी कर्मचारी की सहायता के अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लॉकर का संचालन कर सकेंगे। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वंदे प्रकाश ने कहा कि अहमदाबाद के कालीपुर रेलवे स्टेशन, अर्थात् अहमदाबाद स्टेशन पर पहली बार यात्रियों के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों के पास अक्सर सामान और मूल्यवान वस्तुएँ होती हैं। कई बार उन्हें केवल सामान सुरक्षित रखने के लिए होटल लेना पड़ता है या यदि उन्हें तीन-चार या छह घंटे के लिए किसी कार्यालय या अन्य कार्यस्थल पर जाना हो, तो सामान साथ लेकर जाना असुविधाजनक होता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

लोकोमोटिव शोड साबरमती में “भगवद गीता के जीवन सूत्र” विषय पर प्रेरणादायक व्याख्यान का आयोजन

अहमदाबाद : पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के लोकोमोटिव शोड साबरमती में आज ‘भगवद गीता के जीवन सूत्र: नवानु मुक्त जीवन, स्वस्थ मन और उत्पादक कार्यस्थल’ की ओर एक प्रेरणादायक यात्रा” विषय पर एक अत्यंत ज्ञानसंधक एवं प्रेरणादायक व्याख्यान आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में साबरमती रेलवे अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोजकुमार देव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ मंडल मेकेनिकल इंजीनियर श्री सुमंत प्रसाद गुप्ता, सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर तथा एसोसिएटी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके साथ ही, लोकोमोटिव शोड के सुपरवाइजरों एवं कर्मचारियों ने भी इस आयोजन में



उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अपने मुख्य व्याख्यान में डॉ. मनोजकुमार देव ने भगवद गीता के शाश्वत जीवन मूल्यों एवं सिद्धांतों को दैनिक जीवन तथा आधुनिक कार्यस्थल की परिस्थितियों से जोड़ते हुए नवानु प्रबंधन, मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच तथा



कानूनन आवश्यक है। आरोप है कि नासीरनगर के निवासियों को ऐसी सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति बंद की जाती है तो उसके लिए विधिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। प्रभावित परिवारों की ओर से दायर याचिका में उल्लेख किया गया है कि बिजली आपूर्ति बंद करने से पहले उपभोक्ताओं को लिखित सूचना देना

आवश्यकता बन चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामान्य जीवन की लगभग हर गतिविधि बिजली पर निर्भर है। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट प्रशासनिक आदेश और पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति रोकना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के प्रश्न से जोड़ा गया। याचिका में कहा गया है कि आधुनिक जीवन में बिजली केवल एक सुविधा नहीं बल्कि जीवन की मूलभूत

रख सकेंगे।

डिजिटल लगेज लॉकर की प्रमुख विशेषताएँ

- वर्तमान में प्रथम चरण के अंतर्गत अहमदाबाद स्टेशन पर कुल 59 अत्याधुनिक लॉकर उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुसार तीन श्रेणियाँ—मीडियम, लार्ज और एक्सट्रा लार्ज में विभाजित किया गया है। यह सुविधा यात्रियों के लिए चौबीसों घंटे एवं सप्ताह के सातों दिन (24×7) उपलब्ध रहेगी। इस प्रणाली में निम्नलिखित आधुनिक एवं सुरक्षा संबंधी विशेषताएँ शामिल हैं—

पूर्णातः डिजिटल एवं कैशलेस भुगतान: सुरक्षित लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई (UPI), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ओटीपी (OTP) आधारित एक्सेस: लॉकर के संचालन हेतु यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जिससे अनधिकृत पहुँच पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

मजबूत सुरक्षा व्यवस्था: सभी लॉकर मजबूत एवं छेड़छाड़-रोधी (Tamper-proof) लगेज लॉकर सुविधा का शुभारंभ भारतीय रेल एवं पश्चिम रेलवे की यात्रियों को जाँचनी तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति (UPS) बैकअप की सुविधा भी उपलब्ध है। बहुभाषीय इंटरफ़ेस: देश के विभिन्न भागों

से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल स्क्रीन पर बहुभाषीय इंटरफ़ेस उपलब्ध कराया गया है, जिसे यात्री स्वयं (Self-operated) आसानी से संचालित कर सकते हैं।

लॉकर श्रृंखला		
लॉकर का आकार	3 घंटे तक	6
घंटे तक	24 घंटे तक	40
मीडियम	150	
लार्ज	150	200
एक्सट्रा लार्ज	90	
170	280	

इस आधुनिक सुविधा का संचालन एवं रखरखाव ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से मेसर्स ट्रूपोल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे को सौंपा गया है। पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया गया यह अनुबंध 25 फरवरी 2031 तक प्रभावी रहेगा। इसके अंतर्गत रेलवे को प्रतिवर्ष 8,21,350 का निचरसे अनधिकृत पहुँच पूर्ी तरह प्रतिबंधित रहेगी। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था: सभी लॉकर मजबूत एवं छेड़छाड़-रोधी (Tamper-proof) लगेज लॉकर सुविधा का शुभारंभ भारतीय रेल एवं पश्चिम रेलवे की यात्रियों को जाँचनी तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति (UPS) बैकअप की सुविधा भी उपलब्ध है। बहुभाषीय इंटरफ़ेस: देश के विभिन्न भागों

ग्रीष्मावकाश–2026 में एसटी निगम द्वारा 19,200 एक्सट्रा ट्रिप का संचालन : राज्य के 9 .60 लाख यात्रियों ने की यात्रा

►**प्रधानमंत्री की अपील के परिणामस्वरूप गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में प्रतिदिन 15,000 तक की वृद्धि दर्ज की गई**
►**एसटी निगम द्वारा प्रतिदिन 33,000 ट्रिप्स द्वारा 27 लाख से अधिक यात्रियों को समय पर और सुरक्षित परिवहन सेवा प्रदान की जा रही है**

गांधीनगर : गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ और आवागमन को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों तक आने-जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके; इस उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में एसटी निगम द्वारा इस वर्ष लगभग 19,200 विशेष एक्सट्रा ट्रिप्स का संचालन किया गया। ग्रीष्मावकाश-2026 में 9.60 लाख यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया है।

एसटी निगम द्वारा अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा और गोधरा जैसे जिलों तथा सोमानाथ, द्वारका, पवागढ़, शमलाजी और अंजंजी जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए एक्सट्रा ट्रिप्स का आयोजन किया गया था। राज्य के नागरिक सार्वजनिक सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें और



उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक बने; इस शुभ उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा राज्य को परिवहन सेवाओं में वृद्धि करते हुए 300 नई बसों को तत्काल प्रभाव से जनता की सेवा में लगाया गया था। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की प्रधानमंत्री की अपील के परिणामस्वरूप गुजरात

वडोदरा मंडल में अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस पर रोड यूजर्स को किया गया जागरूक

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा 09 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस (ILCAD) – 2026 मनाया गया। इस अवसर पर संरक्षा विभाग द्वारा रेलवे समपार फाटकों पर सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा असवधानीयता होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से मंडल भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के मार्गदर्शन में संरक्षा विभाग ने सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों के सहयोग से मंडल के विभिन्न समपार फाटकों पर व्यापक जनसंपर्क एवं जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क उपयोगकर्ताओं, पैदल यात्रियों तथा वाहन चालकों को रेलवे सुरक्षा नियमों के पालन एवं सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतापनगर खंड स्थित समपार संख्या-1 स्पेशल पर सुरक्षा जागरूकता नुकड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20 सिविल डिफेंस



स्वयंसेवकों ने भाग लिया। आकर्षक प्रस्तुति के माध्यम से अनधिकृत रूप से रेलवे लाइन पार करने, फाटक बंद होने के दौरान समपार पार करने तथा चेतावनी संकेतों की अनदेखी जैसे खतरनाक व्यवहारों के दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। इसके अतिरिक्त मंडल के विभिन्न समपार फाटकों पर रेलवे कर्मचारियों एवं सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों ने आमजन से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर सुरक्षा संबंधी पंपलेट एवं हैंडबिल

परिवारों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे शामिल हैं, जो अब अस्थायी परिस्थितियों में जीवन यापन करने को विवश हैं। पार्टी का आरोप है कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान मानवीय पहलुओं की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि किसी भी विकासात्मक या नियामकीय कार्रवाई के दौरान प्रभावित लोगों के पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी शासन की जिम्मेदारी होती है।

इस बीच स्थानीय नागरिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि यदि वास्तव में नगर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि कार्रवाई करने वाली एजेंसी कौन थी और उसने किस अधिकार के तहत यह कदम उठाया। साथ ही बिजली आपूर्ति बंद करने के निर्णय की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सके। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर टोरेटर पावर की ओर से संतोषजनक और लिखित जवाब नहीं

दिया जाता है तो प्रभावित परिवार न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पार्टी का कहना है कि इस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण मंच और बिजली उपभोक्ता संरक्षणत निवारण संस्थाओं के समक्ष भी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यदि जवाब नहीं मिला तो इससे पूरे घटनाक्रम में संभावित मिलीभगत की आशंकाएं और मजबूत होंगी। नासीरनगर विवाद अब केवल एक स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह शहरी विकास, पुनर्वास नीति, नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में संबंधित एजेंसियों के जवाब और संभावित कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। फिलहाल प्रभावित परिवार न्याय और पुनर्वास की उम्मीद लगाए हुए हैं, जबकि राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़े हुए हैं।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर बड़ा एक्शन, बीआईएस ने सूरत में की छापेमारी, 112 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जब्त

सूरत। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सूरत में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए बिना अनिवार्य प्रमाणन चिह्न वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का बड़ा जखीरा जन्त किया है। कतारगाम स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर की गई इस छापेमारी ने एक बार फिर बाजार में विक रहे गैर-प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अधिकारियों का मानना ​​है कि ऐसे उत्पाद न केवल कानूनी मानकों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने 9 जून 2026 को कतारगाम क्षेत्र में स्थित एक व्यावसायिक इकाई पर जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जांच की गई, जिनमें कई वस्तुओं पर लगे अनिवार्य बीआईएस पंजीकरण चिह्न और पंजीकरण संख्या अंकित नहीं पाई गई। जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे उत्पाद पंडारित और बिज्की के लिए उपलब्ध थे, जिनके पास आवश्यक प्रमाणन नहीं था। इसके बाद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित उत्पादों को जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान वायरलेस नेकबैंड, वायरलेस ईयरबड्स, पावर बैंक,

चार्जिंग अडैप्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित कुल 112 उत्पाद बहामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार इन सभी उत्पादों पर वह अनिवार्य पंजीकरण विवरण मौजूद नहीं था, जो कानून के तहत आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने ऐसे उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था लागू की है। इसके बावजूद कुछ निर्माता और विक्रेता नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। मोबाइल एप्सेसरीज़, पावर बैंक, चार्जर और वायरलेस उपकरणों का उपयोग लाखों लोग प्रतिदिन करते हैं। ऐसे में यदि इन उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप न हो तो आग लगने, विस्फोट, शॉर्ट सर्किट, बैटरी खराब होने या अन्य तकनीकी दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि सरकार और नियामक संस्थाएँ ऐसे उत्पादों के लिए सख्त गुणवत्ता मानकों को लागू करती हैं।

अधिकारियों ने बताया कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में जारी आदेश के तहत कई इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर बीआईएस पंजीकरण

और मानक चिह्न अनिवार्य किया गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में उपलब्ध उत्पाद निर्धारित सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हों। किसी भी निर्माता, आयातक या विक्रेता के लिए बिना आवश्यक प्रमाणन के ऐसे उत्पादों का निर्माण, भंडारण या विक्रय करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। बीआईएस अधिकारियों के अनुसार वर्तमान समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी का लाभ उठाकर कुछ कारोबारी बिना प्रमाणन वाले उत्पादों को भी बाजार में उतार देते हैं। कई बार उपभोक्ता आकर्षक कीमती या ब्रांड जैसी दिखने वाली पैकेजिंग के कारण ऐसे उत्पाद खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि उत्पाद आवश्यक गुणवत्ता जांच से नहीं गुजरा है। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान, गैर-समय सुरक्षा संबंधी ज़िम्मेां का भी सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत ऐसे मामलों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जानबूझकर बिना अनिवार्य प्रमाणन को वाले उत्पादों का निर्माण, भंडारण या विक्रय करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानून में दोष सिद्ध होने पर कारावास और आर्थिक दंड दोनों का

प्रावधान किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माणों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि बाजार में गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कार्रवाई के बाद बीआईएस ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ब्यूरो का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदते समय उपभोक्ताओं को हमेशा बीआईएस मानक चिह्न और पंजीकरण संख्या की जांच करनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उत्पाद निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। साथ ही व्यापारियों की ओर वितरकों को भी केवल प्रमाणित उत्पादों की खरीद और बिक्री करनी चाहिए ताकि वे कानूनी जटिलताओं से बच सकें। ब्यूरो ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को संदेह हो कि किसी दुकान, गोदाम या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बिना बीआईएस प्रमाणन वाले उत्पादों की बिक्री की जा रही है या बीआईएस चिह्न का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसकी सूचना संबंधित कार्यालय को दी जा सकती है। ऐसी सूचनाएं बाजार में गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ब्यूरो ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल जाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रेल कर्मचारियों के कल्याण एवं उन्हें बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए जूनागढ़ रेलवे परिसर में रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) द्वारा निर्मित 18 टाइप-II रेलवे क्वार्टरों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। सभी क्वार्टर अब उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि जूनागढ़ रेलवे परिसर में प्रस्तावित होटल निर्माण परियोजना के लिए किए गए समझौता ज्ञापन (MOU) के अंतर्गत रेलवे आवासों के प्रतिस्थापन स्वरूप इन क्वार्टरों का निर्माण किया जाना था। विभिन्न कारणों



से वर्ष 2021 से यह कार्य लंबित था। भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में निरंतर समन्वय एवं नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप निर्माण कार्य को गति मिली तथा अंततः इसे सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया। नवनिर्मित 18 टाइप-II क्वार्टर

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इनके उपयोग में आने से रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध होगा। साथ ही कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार, कार्य संतुष्टि में वृद्धि तथा कार्यकुशलता एवं मनोबल को और

सावधानियों, गेटमैन एवं रेलवे कर्मचारियों द्वारा पालन किये जाने वाले निर्देश आदि से सम्बंधित महत्वपूर्ण संदेश दिए गये। वडोदरा मंडल के वरिष्ठ संरक्षा अधिकारी श्री शरद गौतम एवं संरक्षा अधिकारी नवीन यादव के अनुसार इस अभियान को जनता का उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुआ तथा बड़ी संख्या में लोगों तक रेलवे ने संरक्षा व सुरक्षा का संदेश पहुँचाया गया। जागरूकता गतिविधियों, प्रत्यक्ष संवाद और नुकड़ नाटक जैसे प्रभावी माध्यमों के जरिए नागरिकों को सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस-2026 का यह आयोजन वडोदरा मंडल की जनसुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। रेलवे का उद्देश्य केवल रेल संचालन तक सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा व संरक्षा सुनिश्चित करना भी है। जनभागीदारी और जागरूकता को माध्यम से ही सुरक्षित रेलवे एवं सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है।

